ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-12* March-2021
Anthology : The Research

भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय

India's Foreign Policy and International Community

Paper Submission: 05/03/2021, Date of Acceptance: 15/03/2021, Date of Publication: 23/03/2021

प्रमिला कुमारी
शोध छात्रा,
दक्षिण एशिया अध्यन केंद्र,
राजस्थान यूनिवर्सिटी,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्राचीन काल से अपनी परंपरा में समाहित किए हुए है। जिसके प्रभाव से भारत के संबंध विश्व के सभी राष्ट्रों से शांतिपूर्ण बने हुए हैं तथा वर्तमान स्थिति में भारत दक्षिण एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत महाशक्ति बनने के लिए प्रयासरत है तथा एक बड़ी जनसंख्या के कारण विश्व के लिए बड़ा बाजार होने से विश्व संबंधों का मुख्य बिंदु बनता जा रहा है। जिसने भारत के साथ विश्व के घनिष्ठ सम्बन्धों को अपरिहार्य बना दिया है।

The spirit of Vasudhaiva Kutumbakam in India has always been embedded in its tradition since ancient times, due to which India's relations with all the nations of the world have remained peaceful and in the present situation India is an emerging economy in South Asia. And having a large market for the world due to a large population is becoming the main point of world relations, which has made the world's close relations with India inevitable.

मुख्य शब्द : राजनायिक संबंध, नवीन आयाम, द्वीपक्षीय समझौते, कूटनीतिक भागेदारी

प्रस्तावना

किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज और अनेक तथ्यों को समेटे हुए है । जो कभी भारतीय स्वतंत्र आंदोलन से उपजे थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पुराना है। भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध है भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश भी है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं। समय के साथ–साथ भारत के कई भागों में कई अलग अलग राजा रहे भारत का स्वरूप भी बदलता रहा किन्तु वैश्विक तौर पर भारत की विशेषताएं यही है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा हैं। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत में अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। वैश्विक मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा है 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया सामरिक तौर पर भारत ने अपनी शक्ति को बनाए रखा है और विश्व शांति में यथासंभव योगदान देता रहा है। पाकिस्तान व चीन के साथ संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य रहे हैं किंतु रूस के साथ सामरिक संबंधों के अलावा भारत का इजरायल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध रहा है तथा अमेरिका तथा जापान भारत के हिंद महासागर के मुख्य रणनीतिक भागीदार के साथ व्यवसायिक सहयोगी भी रहे हैं। भारत के विभिन्न देशों के साथ वैदेशिक संबंध निम्न प्रकार हैं ।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत के विदेशों के साथ संबंधों से भारतीय राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना।
2. विश्व के अन्य देशों के साथ बाहरी परिवेश बनाकर समावेशी घरेलू विकास के लिए अनुकूल बनाना जिसमें विदेशी भागीदारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के रूप में पर्याप्त साधनों की प्राप्ति संभव हो सके।

3. भारत आतंकवाद, जलवायु, परिवर्तन, निशस्त्रीकरण, भेदभाव रहित विश्व व्यापार व सुशासन की संस्थाओं में सुधार जो भी भारत को प्रभावित करते हैं पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित कर सकें।
4. भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था तथा महाशक्ति बनने के क्रम में वैश्विक मंचों पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक अगुवा के रूप में गिना जाए ।

रूस

सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस से नवीन आयामों पर संबंधों का विकास भारत के साथ हुआ सन 1991 से वर्तमान समय में भारत रूस संबंधों में उतार–चढ़ाव का दौर रहा परंतु कभी कटुता नहीं आई है ।

वर्ष 2000 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा अनुमोदित व्यक्तव्य रूस के इरादों को व्यक्त करता है कि 'अंतरराष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में भारत के साथ अपनी पारंपरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए और दक्षिण एशिया में जारी समस्याओं पर काबू पाने में सहायता करने के लिए और इस क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत के साथ रूसी संबंध विदेश नीति में प्राथमिक दिशा के रूप में माने जाते रहेंगे' के द्वारा भारत के महत्व को दर्शाया गया है। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत रूसी संघ के बीच सामरिक साझेदारी पर घोषणा की तब से वार्षिक आधार पर दोनों देशों के मध्य नियमित शिखर वार्ता हुई है।

नवंबर 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूस यात्रा एवं दिसंबर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने नवंबर 2003 में मास्को की यात्रा की तथा शिखर वार्ता में भाग लिया। मई 2003 में सेंट पीटर्सबर्ग शहर की 300 वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए रूस गए। दिसंबर 2004 में राष्ट्रपति पुतिन ने पांचवें शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा की तथा संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें कैसुलेट मामलों क्षेत्रीय सहयोग ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्रों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा दिसंबर 2009 को रूस यात्रा कर अनेक समझौते संपन्न किए जिनमें दोनों देशों के मध्य परमाणु, सैन्य उत्पाद, हथियारों के कलपुर्जे, तेल उत्खनन और सांस्कृतिक गतिविधि आदि के समझौते हुए। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति के भारत आगमन पर दोनों देशों के बीच भागीदारी को विशेष एवं अधिकार प्राप्त कूटनीतिक भागीदारी स्तर पर पहुंचा दिया। 15वें वार्षिक शिखर बैठक 11 दिसंबर 2014 का आयोजन भारत में होने के कारण रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा, सहयोग, रक्षा, हाइड्रोकार्बन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश पर आपसी सहयोग बना। दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा ''द्रुधवा दोस्ती'' आगामी दशक में सुदृढ़ भागीदारी को अंगीकृत किया। मई 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मास्को की यात्रा कर द्वितीय विश्वयुद्ध की विजय की 70 वीं वर्षगांठ के आयोजन समारोह में भाग लिया। दोनों देशों के अंतर सरकारी आयोग में निरंतर बैठके तथा कार्य प्रगति पर है जिसमें से एक व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग (IRIGCTEC - India-Russian inter - Governmental commission on technical and Economic Cooperation) से संबंधित है जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री व रूसी उप–प्रधानमंत्री स्तर की होती है। दूसरा तकनीकि है (IRIGCMTC – The Indo & Russian inter & Governmental commission on military Technical cooperation) जिसकी से अध्यक्षता रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री स्तर की होती IRIGCTEC के तीसरे सत्र की अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और रूस के उपप्रधान मंत्री श्री दिमित्री रोगोजिन द्वारा की गई थी।

भारत रूस अंतर संसदीय आयोग की तीसरी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के साथ से सह अध्यक्षता करने हेतु रूसी संसद के निचले सदन (राज्य डुमा) के अध्यक्ष 2015 में भारत आए। रूसी राष्ट्रपति द्वारा 17वें वार्षिक सम्मेलन के लिए अक्टूबर 2016 में उन्हें भारत में गोवा का दौरा किया गया। 19 दस्तावेजों का द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आदान–प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में शिखर सम्मेलन में शिरकत करने हेतु सेंट पीटर्सबर्ग रूस की यात्रा की तथा रूस–भारत राजनैतिक संबंधों की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त वक्तव्य तथा रोड मैप जारी किया।

19 वां भारत रूस शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते हुए तथा इसके तुरंत बाद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, भारत–रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ताओं का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ तथा प्रथम भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता (प्टैम्क्) का आयोजन सेंट पीटर्स वर्ग में नवंबर 2018 में हुआ इस वार्ता में भारत की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) रूस की तरफ से आयो ग्रांड मिनिस्ट्री ऑफ इकनोमिक डेवलपमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन द्वारा भाग लिया गया।

दोनों देशों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध, वर्ष 2003–04 में रूस में भारतीय निर्यात 713.76 मिलियन यू एस डॉलर था रूस से आयात 2003 –04 के दौरान 59. 63 मिलियन यूएस डॉलर का रहा जो पिछले वर्ष से 61. 93 प्रतिशत अधिक था। 2007 –08 मे यह 939. 70 मिलियन यूएस डॉलर रहा तथा रूस से किया गया आयात 2468.05 तथा कुल व्यापार 3407.75 मिलियन यूएस डॉलर दोनों देशों के मध्य रहा। वर्ष 2015–16 में कुल कारोबार 6.17 बिलियन यूएस डॉलर व 2016–17 में 7.48 बिलियन यूएस डॉलर रहा ।

फ्रांस

भारत– फ्रांस के संबंध निरंतर परिवर्तित होती रहे हैं फ्रांस इंग्लैंड की भांति भारतीय औपनिवेशिक ताकत रहा है। इंग्लैंड के हटने के बाद फ्रांस ने भारत के साथ आधुनिकीकरण के दौर में व्यापार अर्थव्यवस्था तकनीकि सहायता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परमाणु एवं रक्षा क्षेत्रों में नवीन सहयोग विकसित किए। फ्रांस के साथ भारत के संबंधों को भी उतार–चढ़ाव के कई दौर से गुजरना पड़ा

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-12* March-2021
Anthology : The Research

है। शीत युद्ध तथा अंतरराष्ट्रीय बाधाओं के कारण दोनों देशों के मध्य पिछले दशकों संबंधों में सुधार हुआ है। भारत एवं फ्रांस के संबंधों को युक्तिसंगत भागीदारी के साथ 1998 में जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति के .आर. नारायण ने सन् 2000 में फ्रांस की यात्रा की, वर्ष 2003 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन पियरे रूफिरिन भारत की यात्रा पर रहे। सितंबर 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह फ्रांस की यात्रा पर गए तथा दोनों देशों के मध्य नागरिक क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के संबंधों में एक सहयोग समझौता हुआ। तथा रक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए फ्रांस भारत को नागरिक परमाणु क्षेत्र में सक्षम बनाने वाला प्रथम देश रहा। फरवरी 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति जॉक शिराक भारत की यात्रा पर आए एवं जनवरी 2008 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए।

जुलाई 2009 में फ्रांस के ''वैस्टिल दिवस'' समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री सम्मानित अतिथि के रूप में रहे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी दिसंबर 2010 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। भारत एवं फ्रांस के मध्य परमाणु समझौता संपन्न हुआ जिसमें फ्रांस भारत को परमाणु रिएक्टर मुहैया करवाएगा। इस परमाणु रिएक्टर का प्रयोग जैतापुर परमाणु बिजली घर में इस्तेमाल किया जाएगा। फरवरी 2013 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंक्वासय होल्लाण्डे भारत की राजकीय यात्रा पर है तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान शिक्षा एवं अनुसंधान तथा दीर्घकालिक अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे के सशक्तिकरण हेतु समझौते किए गए। भारत में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अप्रैल 2015 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्वीपक्षीय सहयोग बढ़ाया दोनों देशों के अंतरिक्ष सहयोग के 50 साल पूरे होने की स्मृति में भारत–फ्रांस संयुक्त डाक टिकट का अनावरण किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जनवरी 2016 के 67 वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे ।

दोनों देशों के मध्य द्वीपक्षीय व्यावसायिक सम्बन्धों पर सहयोग तथा राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु समझौता संपन्न हुआ। इसरो और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES के मध्य भारतीय उपग्रह ओशन सेट –3 के साथ आरगोस–4 पेलोड को संबद्ध करने हेतु समझौता संपन्न हुआ। वर्ष 2000 में भारत का निर्यात 1441 मिलीयन यूरो रहा तथा भारत का आयात 938 मिलीयन यूरो रहा । दोनों देशों का कुल व्यापार 2379 मिलीयन यूरो रहा तथा व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। वर्ष 2016–17 के दौरान 10.96 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ 2015–16 के मुकाबले में यह 2.66 बिलियन डॉलर ज्यादा रहा।

अमेरिका

अमेरिका भारतीय गणतंत्र की प्रारंभिक वर्षों के दौरान अमेरिका शायद ही कभी भारत के साथ बहुत संपर्क में रहा। परंतु दोनों राष्ट्र बडे व महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है जिनमें विभिन्न विषमताओं होने के साथ–साथ ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक व राजनीतिक कुछ समानताएं अवश्य मौजूद हैं। भारत की स्वतंत्रता से अब तक इसके अमेरिका के साथ संबंधों का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि दोनों देशों के संबंधों में हमेशा उतार–चढ़ाव की स्थिति रही है।

भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका के द्वारा कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जिन प्रतिबंधों को आंशिक रूप से उठाने की घोषणा बाद में की गई मार्च 2000 में 22 वर्षों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की जो भारत अमेरिकी संबंधों में नया मोड़ साबित हुई। दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौते संपन्न हुए तथा इनसे समझौतों से संबंधित दस्तावेजों को "दृष्टिकोण पत्र 2000" नाम दिया गया। इस यात्रा के दौरान ही भारत अमेरिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना का फैसला लिया गया। 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हमले के बाद राष्ट्रपति बुश ने हिंद महासागर में स्वेज नहर से लेकर सिंगापुर तक रणनीतिक नियंत्रण के लिए भारत के साथ निकटता से सहयोग संबंध कायम किए। सितंबर 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका यात्रा पर रहे दोनों देशों के मध्य ऊर्जा ई–कॉमर्स और बैंकिंग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 6 अरब डॉलर की 5 व्यवसायिक सौदे हुए। आतंकवाद व परमाणु अप्रसार पर द्वीपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की जुलाई 2005 की यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को एक उभरती शक्ति की मान्यता प्रदान कर नाभिकीय ऊर्जा समझौते पर द्विपक्षीय वार्ता तथा समझौता संपन्न हुआ। मार्च 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत यात्रा पर रहे तथा भारत के साथ 2005 के संपन्न परमाणु ऊर्जा समझौते के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस समझौते के अंतर्गत भारत अपने सैन्य व असैन्य उपयोग वाले परमाणु संयंत्रों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (ए।म।) की निगरानी के अधीन लाने को सहमत हुआ। असैन्य परमाणु समझौते के अंतर्गत भारत अपने 22 मौजूदा परमाणु संयंत्रों में से 14 को अंतरराष्ट्रीय निगरानी के अधीन लाएगा तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निगरानी में नहीं लाये जाएंगे।

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने भारत के साथ बनी परमाणु सहमति को स्वीकृति दे दी। अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत से 17 नवंबर 2006 को समझौता (123) की पुष्टि कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के हस्ताक्षर करते ही वित्तीय अधिनियम बन गया। जो यूनाइटेड स्टेट इंडिया न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एंड नॉनप्रॉलीफेरेशन एनहैंसमेंट एक्ट (United States & India nuclear Cooperation Approval and Non Proliferation enhancement act) 2006 नाम से जाना गया। परमाणु सहयोग के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (NSG) की मंजूरी भी आवश्यक होगी। जिससे भारत को असैनिक नाभिकीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने सदस्यों के लिए दिशानिर्देशों को उदार बनाना होगा। एनएसजी की सहमति के बाद इसका सदस्य कोई भी देश भारत को नाभिकीय सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

10 अक्टूबर 2008 को भारत अमेरिका असैनिक नाभिकीय करार पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर कर दिए गए, जो कि जुलाई 2005 के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल की निष्पत्ति था। इस बिल को 28 सितंबर 2008 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तथा 1 अक्टूबर 2008 को सीनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी तथा 18 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस पर हस्ताक्षर किए। तथा इस समझौते को कानूनी रूप प्रदान कर दिया।

नवंबर 2009 में डॉ मनमोहन सिंह ने अमेरिका की यात्रा की तथा अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। असैन्य परमाणु समझौते के क्रियान्वयन पर प्रतिबद्धता जाहिर की दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक साजिदारी के नए चरण की शुरुआत की और इसे ''वैश्विक रणनीतिक साझेदारी'' बताया। नवंबर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच समझौते संपन्न हुए तथा अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु आपूर्ति करता समूह (एनएसजी, NSG) मिसाइल प्रौद्योगिकी, नियंत्रण व्यवस्था, (एमटीसीआर, MTCR) वासेनार व्यवस्था, और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 को अमेरिका की यात्रा की तथा आर्थिक रक्षा कारोबार निवेश के मुद्दों पर वार्ता हुई अनेक समझौते संपन्न हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारतीय राजन्य संबंधी रणनीति पर अमेरिका द्वारा समर्थन किया गया तथा सिलीकान वैली के दिग्गजों से मुलाकात कर "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की द्वारा भारत निर्माण में अमेरिकी कंपनियों के सहयोग का आह्वान किया गया।

जनवरी 2015 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए यह प्रथम अवसर रहा जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल किया गया। दोनों देशों द्वारा समुद्री परिवहन, सामुद्रिक सुरक्षा, हवाई सुरक्षा पर साथ मिलकर कार्य करने पर सहमति के साथ 10 वर्षों के लिएष ''अमेरिकी भारत रक्षा समझौते'' का नवीनीकरण किया गया तथा असैन्य परमाणु समझौते में आ रही रुकावटों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति मदद का भरोसा दिलाया। सितंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुनः अमेरिका की यात्रा की तथा यात्रा के दौरान सिलिकॉन वैली का दौरा किया जिसमे डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ाबा देने के साथ साथ अमेरिकी प्रोद्धोगिकि क्षेत्र के साथ सम्बन्धों को गहरा कर भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाबा देने का लक्ष्य रखा। जनवरी 2017 में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तथा नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर रहे।

दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध

2001 में दोनों देशों के मध्य कुल व्यापार 13.29 बिलियन यू एस डॉलर रहा। जिसमें आया 3.5 बिलियन यूएस डॉलर तथा निर्यात 9.7 मिलियन यूएस डॉलर रहा जो वर्ष 2008 में बढ़कर भारत का आयात 17.6 बिलियन यूएस डॉलर तथा निर्यात 25.7 बिलियन यूएस डॉलर दोनों देशों का कुल व्यापार 43. 8 बिलियन यूएस डॉलर 2015 में अमेरिका से निर्यात 39.7 बिलियन यूएस डॉलर भारत से आयात 69.6 बिलियन यूएस डॉलर तथा दोनों देशों के मध्य कुल व्यापार 109.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

जापान

जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है, भारत–जापान के संबंध कई चरणों से होकर गुजरे हैं भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों एक समान राजनीतिक प्रणाली एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्था के बावजूद दोनों देशों के संबंध अधिक नहीं रहे हैं। 1952 से प्रारंभ औपचारिक संबंधों के बजाय भारत और जापान के बीच दूरी बनी रही। 21वीं सदी के आरंभ में दोनों देशों की राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार हुए जापानी प्रधानमंत्री मोरी की वर्ष 2000 में महत्वपूर्ण भारत यात्रा के दौरान 21वीं सदी में भारत जापान के वैश्विक साझेदारी शुरू की गई। इससे पूर्व परमाणु परीक्षणों के बाद जापान ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक एवं तकनीकि सहायता रद्द कर दी थी लेकिन वर्ष 2002 से जापान का नजरिया बदलने लगा था तथा भारत के साथ सहयोग प्रक्रिया को बहाल किया वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जापान यात्रा की तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ वार्षिक शिखर बैठक के प्रावधानों के साथ वैश्विक एवं सामरिक साझेदारी के रूप में संबंधों को स्तरोन्नत किया तथा भारत जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार संपन्न किए। नवंबर दिसंबर 2013 में जापानी सम्राट अकीहितो ने भारत की यात्रा की जिससे दोनों देशों के संबंधों में घनिष्ठता बढी। वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवनिर्वाचित जापानी प्रधानमंत्री तारो आसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा जापान ने भारत के साथ दिल्ली मुंबई रेलवे परियोजना के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आठवीं वार्षिक शिखर बैठक में प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारत दौरे पर जनवरी 2014 में आए तथा दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ 9वी वार्षिक शिखर बैठक के लिए सितंबर 2014 के दौरान जापान का दौरा किया तथा भारत में एक जापान ''निवेश संवर्धन साझेदारी'' शुरू की गई जिसके तहत जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की मंशा रखी। विदेश मंत्री स्तरीय आठवीं सामरिक वार्ता 17 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई। जिसमें आपसी हितों के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई जापानी प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2015 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों के मध्य द्वीपक्षीय भागीदारी की ओर बढ़ने तथा विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी पर चर्चा के साथ ही साथ मुंबई अहमदाबाद रूट पर जापान हाई स्पीड रेल (HSR) प्रौद्योगिकी को लागू करने हेतु समझौता संपन्न हुए जिसमें 100 बिलियन येन की जापानी आधिकारिक विकास

सहायता (ओ डी ए) ऋण प्रदान किए। 10 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर रहे तथा नाभिकीय ऊर्जा पर एक समझौता संपन्न हुआ। इस सौदे में जापान से भारत को परमाणु रिएक्टर ईंधन और प्रौद्योगिकी आपूर्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस सौदा द्वारा दिल्ली में योजनाबद्ध 6 परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद मिलेगी जिसे 2032 तक पूरा किया जाएगा। सितंबर 2017 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे गांधीनगर में आयोजित 12वीं भारत–जापान वार्षिक बैठक में भाग लेने आए तथा दोनों प्रधानमंत्रियों ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया ।अलंग सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को अपग्रेड करने के लिए जापान द्वारा 76 मिलियन डॉलर ऋण उपलब्ध किया तथा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी जापानी कंपनी सुजुकी ने स्थापित की जिसमें 3800 करोड़ का निवेश सुजुकी द्वारा किया गया।

दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध

वर्ष 2013–14 में भारत–जापान विपक्ष व्यापार 16.31 बिलियन यूएस डॉलर पर था जो पिछले वर्ष में 18 .5 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 11.89 प्रतिशत कम है वर्ष 2016–17 में भारत से जापान को निर्यात 86 बिलियन डॉलर था जब की समान अवधि में आयात 9.76 बिलियन डॉलर रहा।

इजराइल इजराइल मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण अत्यंत लघु यहूदी राष्ट्र है इसका अधिकांश भाग रेतीला है लेकिन इजरायल लोगों के परिश्रम ने इस राष्ट्र को हरे भरे रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

इजरायल की स्थापना के बाद 1950 में भारत ने उसे मान्यता प्रदान की लेकिन इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। 29 जनवरी 1992 में भारत इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की घोषणा की तथा नई दिल्ली और तेल अवीव ने अपने दूतावास खोलने की औपचारिकताएं पूरी की सितंबर 2002 में एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल का दौरा किया जो पूर्ण भारत इजराइल संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक में भाग लेने रक्षा सचिव के नेतृत्व में गए थे तथा दूसरी बैठक में नई दिल्ली में मई 2002 में आयोजित हुई 8 दिसंबर 2003 को इजरायल के प्रधानमंत्री शेरोन भारत यात्रा पर आए। भारत आने वाले पहले प्रधानमंत्री थी तथा दोनों देशों के मध्य विज्ञान एवं तकनीकि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते हुए। दिसंबर 2004 में इजराइली उप–प्रधानमंत्री ऐहद अलर्ट ने जो उद्योग व्यापार एवं श्रम तथा संचार मामलों के मंत्री थे एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की 2005 में भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कपिल सिब्बल ने इजरायल का दौरा किया इस यात्रा के दौरान हुए समझौतों में दोनों पक्षों ने उद्यमियों को जोखिम मुक्त अनुदान देने के लिए एक–एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। नवंबर 2005 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ इजरायल यात्रा पर रहे, तब एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप (जेएससी) का गठन हुआ।

जिससे 2005 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 मिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मार्च 2006 में एग्रीटेक प्रदर्शनी के अवसर पर भारतीय कृषि मंत्री शरद पवार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल का दौरा किया जिसमें नागालैंड गुजरात व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। दिसंबर 2006 में इजराइली उप–प्रधानमंत्री और व्यापार उद्योग एवं श्रम मामलों के मंत्री श्री एलियरू येच्चाय ने 50 प्रमुख इजराइली उद्यमियों के साथ भारत का दौरा किया। 2007 में इजराइली उप–प्रधानमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री श्री शॉल मॉफिज के साथ इजराइल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया। कृषि तथा उद्योग व्यापार एवं श्रम मंत्री विनियमन वेल एलिजट जनवरी 2010 में भारत यात्रा पर रहे जनवरी 2012 तथा अप्रैल 2012 में भारतीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा तथा भारतीय सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने इजरायल के राजकीय दौरे किए।

मई 2014 में नई सरकार बनने पर इजरायल के साथ भारत के संबंधों में नई शुरुआत हुई, जिसमें पहला कदम नवंबर 2014 को भारतीय गृह मंत्री ने इजरायल की यात्रा कर उठाया। जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू से मुलाकात की तथा दोनों देशों के बीच सहयोग पर वार्ता हुई। फरवरी 2015 में इजरायली रक्षा मंत्री मोशो ओलन ने भारत की यात्रा की अक्टूबर 2015 के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के साथ इजरायल का दौरा किया। दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते संपन्न हुए। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर 15 नवंबर 2016 को इजरायली राष्ट्रपति श्री रूबेन रिवलिन ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की। बीस से अधिक समझौते संपन्न हुए। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल का द्वारा संपन्न किया गया। जिसमें औद्योगिक अनुसंधान कि ओर विकास, जल संरक्षण, परमाणु ऊर्जा, GEO-LFO ऑप्टिकल लिंक, लघु उपग्रह आदि से संबंधित समझौते संपन्न हुए भारत इजरायल संबंधों की 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में जनवरी 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने भारत की यात्रा की तथा साथ में एक 130 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर रहा। दोनों देशों के मध्य साइबर सुरक्षा, तेल, गैस, उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में समझौते संपन्न हुए।

दोनों देशों के मध्य व्यापार–वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य व्यापार 200 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में बढा है वर्ष 2018–19 कुल द्वीपक्षीय व्यापार मे 5.65 बिलियन यूएस डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुंच गया। जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विश्व व्यवस्था में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन आ रहे

हैं। भारतीय विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सार्थक संबंधों पर बल देती है ताकि राष्ट्रीय आर्थिक बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता और भौगोलिक एकता सहित अपने मुख्य लक्षणों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपनी मुख्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंताओं का समाधान कर सके भारत ने अपने पड़ोसी और सार्क देशों के पास अपने संपर्कों को गहन किया है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, इजरायल तथा विश्व के अन्य देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी के आर्थिक और राजनीतिक आधारों को सुदृढ़ और विकसित किया है।

विगत कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा था कि भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है। भारत अपनी विदेश नीति को सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त कर बहु वैकल्पिक बनाया जाये। राजनय के राष्ट्रीहितों को अनुकूल बनाया जाए, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए राजनय का विकास किया जाए, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का विकास किया जाए भारत आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ रिश्ते बना रहा है। वर्तमान समय में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है।

पड़ोसी देशों के साथ विश्वास पूर्ण संबंधित का संबंधों के कार्यक्रम का स्वागत किया जाए। यदि ऐसा करने से भारत शांति एवं समझ से काम ले तो भारत की विदेश नीति अपनी आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी और विश्व के सभी देशों के साथ मधुर सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास कर सकेगी।

संदर्भ सूची ग्रंथ

1. *राजेश मिश्रा, भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति, ओरिएंट ब्लाक स्वान , 2016*
2. *डॉक्टर अनिल कुमार बी. हालु, फॉरेन पॉलिसी ऑफ़ इंडिया, इशिका पब्लिकेशन हाउस जयपुर, 2015*
3. *आर एस यादव, भारतीय विदेश नीति, डार्लिंग किंडरस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2013*
4. *जे एन दीक्षित, रहीस सिंह, भारत की विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन*
5. *डॉक्टर पुष्पेश पंत, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सिद्धांत और व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2019*
6. *नवीन भारद्वाज, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन कंटेंपरेरी वर्ल्ड, रीगल प्रकाशन 2014*
7. *बी एल फड़िया, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक साहित्य भवन, पब्लिकेशन आगरा 2000*
8. *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं सिद्धान्त एवं व्यवहार, डॉ प्रभुदत्त शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2016*
9. *https://usembassy.gov>business*
10. *www.icwa.in03july2019*
11. *www.bbc.com*